श्री कपिल वर्मा : यह कम्पलेंट बहुत ज्यादा हैं।

श्री जनेश्वर मिश्र : उनकी जांच कराई जाती है और जांच कराने पर ज्यादातर शिकायतें गलत पाई जाती हैं। इसके लिए कम्प्यूटर की व्यवस्था की गई है। माननीय सदस्य और उपभोक्ता दोनों इस पर एतराज करते है कि कम्प्यूटर से जो हमारी एस. टी. डी. बातें होती हैं उसको बिलिंग और रिपोर्ट आम तौर पर न दिया करें क्योंकि उससे सिक्रेसी खत्म होती है, लेकिन फिर भी हम लोग इस बारे में सतर्क हैं कि कोई ऐसी शिकायत न हो।

श्री कपिल वर्मा : कम्प्यूटर तो इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में लगते हैं, सब जगह नहीं लग सकता और वही रिकार्ड करता है, लेकिन यह कालें जनरल लाइनमैन मिला देते हैं और इसमें गड़बड़ होती है। आप आप स्टाफ से बात करेंगे, आप तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, इलाहाबाद, लखनऊ, सब जगह जानते हैं। यह बहुत वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस है कि लाइनमैन पैसा लेकर के ट्रांसफर कर देते हैं।

श्री **सभापति** : आपने इलाहाबाद, लखनऊ की बात की, वहां पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज है।

कुमारी आलिया : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट एक सेंसेटिव जगह है लेकिन वहां पर आम शिकायत यह है कि टेलीफोन सुविधा बिल्कुल हैन्डआ पड़ी हुई है। यहां पर एस. एस. पी. को यह शिकायत रहती है। मुझसे उन्होंने कहा कि आप टेलीफोन कम्युनिकेशन समिति में हैं और वहां का टेलीफोन खराब चलता रहता है। दूसरे, वहां पर इलेक्ट्रोनिक्स सिस्टम हो गया था। क्या मिनिस्टर साहब यह बताने का कष्ट करेंगे कि पिछली सरकार ने इसे कब इलेक्ट्रोनिक्स किया ? लेकिन आज तक वहां काम शुरू नहीं हुआ है तो कार्य कब तक शुरू करवाने के लिये मेहरबानी करेंगे ?

श्री जनेश्वर मिश्र : महोदय, हमसे उत्तर प्रदेश के होम सक्रेटरी ने यह शिकायत की थी कि फैजाबाद के कलैक्टर और कप्तान से होट लाईन पर हमारी बात नहीं हो पाती और फैजाबाद में अयोध्या पड़ता है जिसका विवाद इस समय सारे देश में छिड़ा है। उसके बाद हमने आदेश दिया और वहां एक सौ-डाट का इलेक्ट्रोनिक्स एक्सचेंज एलौट हो गया है। जल्दी ही लग जायेगा और अधिकारियों से बात करने के लिये लखनऊ से होट लाईन की व्यवस्था की गयी है।

उत्तर पूर्व परिषद का राज्य स्तरीय कार्यालय

*282. **श्री नारायण कार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्व परिषद की योजनाओं को क्रियान्वयन की सभी संबंधित राज्यों में निगरानी रखने के लिये उत्तर पूर्व परिषद का राज्य स्तर का कार्यालय स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और उत्तर पूर्व परिषद द्वारा त्रिपुरा में जिस सड़क का निर्माण शुरू किया गया था उसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुबोध कान्त सहाय) (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है। त्रिपुरा राज्य में सड़कों के निर्माण के बारे में उपलब्ध सूचना संलग्न है।

विवरण

त्रिपुरा राज्य के लिए सीमा सड़क विकास बोर्ड के कार्यक्रम में निम्नलिखित पांच सड़कें सम्मिलित हैं:—

(i) मनु-कंचनपुर	29.36 कि. मी.
(ii) खार्मातगबाड़ी-नालंगाबाड़ी	21.50 कि. मी.
(iii) मनु-चमनु-गोबिंदबाड़ी	58.76 कि. मी.
(iv) खुशीदनपारा-चमनु	34.88 कि. मी.
(v) गोबिंदबारी-फुलडुंगसेई	53.00 कि. मी.

क्रम संख्या (i) से (iv) पर उल्लिखित चार सड़कें जोड़ी जा चुकी हैं। और उन्हें चौरस बनाने का शेष कार्य और क्लास–9 सरफ़ेस स्पैसीफ़िकेशन के लिए बचाव कार्य/नालियों का कार्य, अर्ध-स्थायी पुलों का कार्य वर्ष 1993 के अंत तक पूरा किया जाना है। जहां तक क्र. सं. (v) पर उल्लिखित सड़क का संबंध है, 53 कि० मी० लम्बी सड़क में से पहले 10 कि० मी० सड़क का निर्माण कर दिया गया है – शेष भाग 1996 तक पूरा किया जाना है।

इसके अतिरिक्त राज्य लोक निर्माण विभाग के कार्यक्रम में निम्नलिखित चार सड़कें सम्मिलित की गयी हैं।

क्र.स.	सड़क/योजना का नाम	लम्बाई	पूरा होने की सम्भावित तारीख
1.	आईजोल बंधमुन-कुमारघाट	72 कि. मी.	पुल को छोड़कर मार्च 1992 तक
2.	तिलथाई-धमचेरा-तिउपाईबारी	122 कि. मी.	पुल को छोड़कर मार्च 1992 तक
3.	खेदाचेर-दमचेर	25 कि. मी.	पुल को छोड़कर मार्च 1992 तक
4.	पिचारथाल-चेबरी	94 कि. मी.	पुल को छोड़कर मार्च, 199 तक

SHRI NARAYAN KAR: Mr. Chairman, Sir, may I know from the hon. Minister whether it is a fact that there is no minitoring system within the North-Eastern Council States and funds provided to this region remain unexpended due to the non-availability of monitoring system? It is a matter of great regret that even after 42 years of our independence the North-Eastern region remains disconnected from the mainland of India. Not only that, within the North-Eastern States there is no link between one State and another State. May I know from the Minister whether the Government has any proposal for construction of a bridge over the river Lungai to connect Mizoram with Tripura?

श्री सुबोध कान्त सहाय : सभापति महोदय, ऐसी बात नहीं है कि वहां निगरानी की व्यवस्था नहीं है । परिषद की योजनाओं पर निगरानी के लिये राज्यों से परिषद की जो सलाहकार समिति, जो सलाहकार हैं वही करते हैं, क्योंकि हर एक राज्यों के लिये कोई निगरानी व्यवस्था अलग से करने पर एक एडीशनल खर्च होगा और सबसे ज्यादा राज्य सरकारें स्वयं योजनाओं को कार्यान्वित कराने के लिये तत्पर रहती हैं । इसलिये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । माननीय सदस्य ने जिस स्पेसिफिक योजना के संबंध में कहा है वह योजना अगर एन० ई० कौंसिल के तहत होगी तो उस पर कार्यवाई कराने की कोशिश की जायेगी ।

श्री सभापति : कोई पुल के लिये कहा है विशेष रूप से ।

SHRI NARAYAN KAR: The funds remain unexpended.

श्री सभापति : उनका कहना है कि बहुत से फंड जो वहां एलौट होते हैं।

They are not expended.

श्री सुबोध कान्त सहाय : नहीं सर।

MR. CHAIRMAN: He wants that some method should be found out so that the funds provided are fully utilised for that purpose. That is all.

श्री सुबोध कान्त सहाय : नहीं सर, त्रिपुरा की जिस योजना के संबंध थे यह बता रहे हैं.... (व्यवधान)

Mr. CHAIRMAN: नहीं, दो हिस्से हैं—

First he says that the funds allotted to this region under various schemes remain unexpended. That is why the region has remained backward. Are you thinking of doing something so that funds are not left and they are properly utilised? That was his question. The second question is about the bridge.

श्री सुबोध कान्त सहाय : नहीं सर, मेरे ख्याल से जिस योजना के तहत फंड दिये गये हैं उसका प्रोपर उपयोग किया जा रहा है ।

MR. CHAIRMAN: No lapsing.

SHRI NARAYAN KAR: Mr. Chairman, Sir, as you are aware of the fact that Tripura has no railway line within the State and the only communication is through roads. Is the Government aware of the fact that National highway which is the life-line of the Trupura—most of the permanent bridge and semi permanent bridges are in deplorable condition and the construction being disturbed due to the non-availability of funds. May I know from the Minister whether the Government has any proposal to allocate necessary funds from the N.E.C. for construction of this bridge? The Minister has stated in his reply that construction of roads will be completed bp March, 1992 excluding the bridge. The roads cannot become full until the bridge is constructed and it cannot be opened for communication by March, 2000. May I know from the Minister whether this connection is being hampered for financial constraints?

श्री सुबोध कान्त सहाय : श्रीमन, फाइनेंशियल कांस्ट्रेंट के चलते यह काम नहीं रुका है क्योंकि फाइव इयर प्लान के सबसे लास्ट में यह योजना रखी गई थी। उस पर काम हो रहा है, दो पुल बन चुके हैं और दो पुलों का निर्माण होने जा रहा है। 1992 तक की उसकी अवधि है, तब तक यह काम पूरा हो जाएगा।

SHRI KHYOMO LOTHA: Sir, I think the proposal in part (a) of the question to set up a state-level office to monitor the implementation of the projects under the North-Eastern Council is a good proposal. I feel that the Government should take it into consideration.

MR. CHAIRMAN: The answer is 'no'.

SHRI KHYOMO LOTHA: I am requesting that it should be considered. The other aspect of it is that the M.Ps. from the North-East should also be taken into confidence and also involved in this North-Eastern Council. They are never invited. I think the other North-Eastern M.Ps. will agree with me.

The construction of a road from Dimapur to Naginimara is going on in Nagaland. It is known as the Foothill Road. The construction of this road was taken up several years ago. But the progress is very slow because the Assam Government is opposing the construction of this road. So I want an assurance from the Government that Assam will be told in clear terms that as far as this road is concerned, they should not oppose. They say that it passes through disputed lands. Even if it is so under that excuse or pretext of disputed lands the development of the road and communication should not be stopped. I want an assurance from the Minister.

As for the Rs. 1500 crores sanctioned this time for the Eighth Five Year Plan the split state-wise break-up of the fund allocation should have been given to us. The break-up figures should be given to us. I want to know these things from the Minister Sir.

श्री सुबोध कान्त सहाय : महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने एन० ई० सी० की कार्यवाही में इनके सहयोग का सवाल उठाया है, यह एक अच्छा सुझाव है कि उस इलाके के संसद सदस्यों की भी राय ली जा सके, इस पर सरकार विचार करेगी।

8वीं पंचवर्षीय योजना अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन सरकार ने 7वीं योजना में करीब साढ़े सात करोड़ रुपया दिया था, हमारी सरकार ने दुगना करने का प्रयास किया है और 1500 करोड़ का प्रपोजल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी दो दिन पहले जब नार्थ ईस्ट काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने एश्योरेंस दी है। मैं समझता हूं कि उसके बाद उसका ब्रेक अप दिया जा सकता है, उसकी रूपरेखा बताई जा सकती है।

SHRI KHYOMO LOTHA: What about the construction of the road I mentioned?

श्री सुबोध कान्त सहाय : जिस रोड के संबंध में माननीय सदस्य ने कहा है, इसमें लैंड ऐक्विजिशन का सवाल रुका हुआ है। यह सही है कि दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों के बीच में यह सवाल आएगा और उनके साथ इस मामले को हल कराया जाएगा।

SHRI G. G. SWELL: The North-Eastern Council have just had a very high-profile meeting in Guwahati the other day which was attended by about four Union Cabinet Ministers in which it seems that some decision was taken to substantially augment the funds of the North-Eastern Council. I believe this will go a long way towards meeting the needs of the Narth Eastern region. Now he North-Eastern Council headquarters are situated in Shillong. And it is cramped for space. I would like to know from

the Minister whether the North Eastern Council had been negotiating with the land owners for the acquisition and the purchase of about 200 acres of land in the vicinity of Shillong to accommodate the complex of its different offices.

श्री सुबोध कान्त सहाय : सभापति महोदय, यह सही है कि सेक्रटरिएट को पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए सरकार इस दिशा में कार्यवाही कर रही है और नगोशिएशन भी चल रहा है। अभी पिछली मीटिंग में ही, जो दो दिन पहले हुई थी, इस पर चर्चा हुई है लेकिन अभी कोई ठोस रूपरेखा सामने नहीं है।

SHRI G. G. SWELL: I would like to know whether they are negotiating for the acquisition or purchase of 200 acres of land in the vicinity of Shillong. It is my specific question.

श्री सुबोध कान्त सहाय : नैगोशिएशन के बारे में मैंने कहा कि नैगोशिएशन तो जरूर चल रहा है लेकिन कोई शेपइसने नहीं ली है। इसलिए इसके बारे में मैं अभी कोई जवाब नहीं दे सकता।

DR. NAGEN SAIKIA: Sir, there is a long-standing demand of Assam to have a bridge over Brahmaputra near Bogivil at Dibrugarh. And its people and many organisations have approached the Government of India many times. I want to know from the hon. Minister whether he will consider a project to construct the bridge over Brahmaputra near Bogivil at Dibrugarh.

श्री सुबोध कान्त सहाय : उपसभापति महोदय, यह जो एन० ई० सी० में फैसला हो गया है, इसे संबंधित मंत्रालय को कार्यवाही के लिए भेजा जा रहा है।

श्री सभापति : यानी आपने इसे सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है।

श्री सुबोध कान्त सहाय : जी हां।

ब्रिटेन से आने वालों के लिये वीजा के नियमों में परिवर्तन

*283. **श्री सुरेश पचौरी** :
श्रीमती मारग्रेट आल्वा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन से भारत आने वालों के लिये वीजा नियम हाल में बदल दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल) (क) हाल ही में हमने विदेशी राष्ट्रिकों के एक विशेष वर्ग के संबंध में अपनी वीजा नीति को उदार बनाया है जिसमें ब्रिटिश नागरिक भी शामिल हैं जो अक्सर भारत में आते हैं।

(ख) यह उदारता वस्तुतः हमारी वीजा नीति के सामान्य स्वरूप का ही एक हिस्सा है।

श्री सुरेश पचौरी : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ब्रिटिश-नागरिकों के लिए वीसा नीति में संशोधन किया गया? क्या ब्रिटिश सरकार भी, जो भारतवासी वहां जाना चाहते हैं उन्हें वीसा देने में ऐसी ही समानता का रुख अपनाते हुए उदारता बरतेगी? क्या ऐसा कोई अनुबंध भारत सरकार ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ किया है? वीसा नीति को उदार करने से भारत को क्या लाभ पहुंचा है? वीसा नीति के उदार बनने के बाद क्या भारत में आने वाले ब्रिटिश-नागरिकों की संख्या में वृद्धि हुई है? क्या उदार वीसा नीति के तहत ही "ऐमनैस्टी इंटरनेशनल" को भारत में आने की इजाजत दी गई?

---

*सभा में यह प्रश्न श्री सुरेश पचौरी द्वारा पूछा गया।